[न रिश्वत लेंगे, न रिश्वत देंगे] मुंबई, मंगलवार, 23 जून 2026 । मूल्य 0.00, कुल पृष्ठ 4 [वर्ष: 12, डिजिटल अंक: 241, प्रधान संपादक : पवन जैन पदमावत] +91-9594542679 www.padmavatmedia.in padmavatmedia@gmail.com

दैनिक हिन्दी राष्ट्रीय डिजिटल समाचार पत्र

पदमावत मीडिया

Reg. No. MH180326353

अनमोल वचन

काम की समाप्ति संतोषप्रद हो तो परिश्रम की थकान याद नहीं रहती।

जिला आधारित विकास मॉडल 02

डिजिटल संस्करण महाराष्ट्र व राजस्थान से प्रकाशित

03 सांगानेर थाने पहुंचे ...

खबर संक्षेप

26 वर्ष पुरानी राजस्व त्रुटि का हुआ समाधान

राजसमंद @ पदमावत मीडिया। कुंभलगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत गजपुर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में 26 वर्षों से

लंबित राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटि का समाधान कर रामलाल भील को राहत प्रदान की गई। रामलाल पुत्र बरदा भील के भूमि अभिलेखों में वर्ष 2000 में विरासत दर्ज करते समय नाम संबंधी त्रुटि हो गई थी, जिसके कारण उन्हें विभिन्न राजस्व कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीण सेवा शिविर में उन्होंने अपनी समस्या प्रस्तुत की, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग ने प्रकरण की जांच की। तहसीलदार पर्वत सिंह राठौड़, भू-अभिलेख निरीक्षक गोविंद सिंह चौहान एवं संबंधित कार्मिकों ने दस्तावेजों का सत्यापन कर मौके पर ही नाम शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी की तथा संशोधित जमाबंदी की प्रति रामलाल को उपलब्ध कराई। वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होने पर रामलाल एवं उनके परिवार ने खुशी जताते हुए राज्य सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान कर उन्हें राहत प्रदान की जा रही है।

रिवर फ्रंट गार्डन में वरिष्ठ नागरिकों ने मनाया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

उदयपुर @ पदमावत मीडिया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रिवर फ्रंट गार्डन में सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों ने

उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया। योग प्रशिक्षक भावना जैन एवं उनकी टीम के निर्देशन में प्रतिभागियों ने करीब एक घंटे तक योग, व्यायाम एवं एक्यूप्रेशर का अभ्यास किया। भावना जैन ने वरिष्ठ नागरिकों के उत्साह और नियमित अभ्यास की सराहना करते हुए कहा कि यहां निरंतर किए जा रहे योग एवं व्यायाम से सभी में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। कार्यक्रम में पूर्व महापौर रजनी डांगी भी उपस्थित रहीं। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों का उत्साहवर्धन किया तथा महिलाओं के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुति में भाग लिया। इस अवसर पर फादर्स डे भी मनाया गया, जिसमें वरिष्ठ पिताओं का उनके पुत्र-पुत्रियों द्वारा माल्यार्पण एवं सम्मान किया गया। संस्था अध्यक्ष सुरेश वाधवानी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी को नियमित योग अपनाने के लिए प्रेरित किया। अंत में सचिव सुभाष अग्रवाल ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, देशी बंदूक व कारतूस बरामद

बालोतरा @ पदमावत मीडिया। जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे

विशेष अभियान के तहत गुड़ामालानी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देशी टोपीदार बंदूक, नौ सीसे के छर्रे एवं नौ टोपियां बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक रमेश ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरफूल सिंह एवं वृत्ताधिकारी सुखाराम के सुपरविजन में थानाधिकारी सुरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि गुड़ामालानी कस्बे के मेला मैदान क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ा। तलाशी में उसके कब्जे से अवैध देशी टोपीदार बंदूक, नौ सीसे के छर्रे तथा नौ टोपियां बरामद हुईं। पूछताछ में वह हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने हथियार जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी महेश चौधरी पुत्र रामाराम, निवासी देशांतरीयों का वास, गुड़ामालानी है।

कुंभलगढ़ और टाइगर रिजर्व की बहस:

संरक्षण या एक गंभीर भूल?

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

राजस्थान के कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव अब केवल वन्यजीव संरक्षण का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक विमर्शों में से एक बन चुका है। एक ओर वे लोग हैं जो बाघों की पुनर्स्थापना को संरक्षण की बड़ी उपलब्धि और गौरव का विषय मानते हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय समुदाय, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग, स्वतंत्र शोधकर्ता तथा अनेक वन्यजीव विशेषज्ञ यह प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या कुंभलगढ़ वास्तव में दीर्घकालिक रूप से बाघों की एक स्वस्थ और स्थायी आबादी को सहारा देने के लिए उपयुक्त है?

वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि बाघ एक अद्भुत और संरक्षण योग्य प्राणी है या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाघ भारत की प्राकृतिक धरोहर का गौरव है।

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वर्ष 2026 का कुंभलगढ़ बाघों के लिए सही परिदृश्य है? यदि संरक्षण भावनाओं के बजाय विज्ञान और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, तो इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार होना आवश्यक है।

प्रतिष्ठा का आकर्षण: आखिर कुंभलगढ़ में बाघ क्यों लाना चाहते हैं कुछ लोग? इसमें कोई दो राय नहीं कि बाघ का अपना एक विशेष आकर्षण और प्रतीकात्मक महत्व है।

किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने से प्राय: प्राप्त होते हैं–

- राष्ट्रीय स्तर पर पहचान
- सरकारी वित्तीय सहायता
- संरक्षण परियोजनाओं के लिए अनुदान
- वैज्ञानिक शोध एवं अध्ययन
- अंतरराष्ट्रीय ध्यान और प्रतिष्ठा

समर्थकों का तर्क है कि कुंभलगढ़ का वन क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों में से एक है और बाघों की मौजूदगी से इसकी संरक्षणात्मक स्थिति और मजबूत होगी। सर्वेक्षणों में सांभर, नीलगाय तथा अन्य शिकार प्रजातियों की उपस्थिति भी दर्ज की गई है।

ये तर्क अपने स्थान पर उचित हैं।

किन्तु बाघ संरक्षण केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई परिदृश्य आने वाली कई पीढ़ियों तक बाघों को प्राकृतिक रूप से जीवित रख सके, बिना लगातार मानवीय हस्तक्षेप के।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न:

- क्या कुंभलगढ़ स्वाभाविक रूप से बाघों को सहारा दे सकता है?
- कई वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि इसका उत्तर अभी स्पष्ट नहीं है।

विशेषज्ञ समितियों ने संकेत दिया है कि वर्तमान स्वरूप में कुंभलगढ़-टोडगढ़ परिदृश्य को दीर्घकालिक रूप से एक व्यवहार्य बाघ आबादी के लिए और अधिक आवास सुधार तथा शिकार प्रजातियों की वृद्धि की आवश्यकता है। यह समझना आवश्यक है कि टाइगर रिजर्व केवल ऐसा जंगल नहीं होता जहाँ कोई एक बाघ जीवित रह सके।

उसे ऐसा परिदृश्य होना चाहिए जहाँ–

- बाघ सफलतापूर्वक प्रजनन कर सकें।
- शावक वयस्कता तक पहुँच सकें।
- नए क्षेत्र विकसित हो सकें।
- आनुवंशिक विविधता बनी रहे।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनतम रहे।

यशवर्धन राणावत
संभागीय अध्यक्ष
अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन

एक अकेला बाघ अनेक जंगलों में जीवित रह सकता है। लेकिन बाघों की स्थायी आबादी बनाना कहीं अधिक कठिन कार्य है।

कुंभलगढ़ की पहचान कभी बाघ–केंद्रित नहीं रही

ऐतिहासिक रूप से कुंभलगढ़ अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता रहा है, जिसमें शामिल हैं–

तेंदुए, भेड़िये, स्लॉथ भालू, नील गाय, लकड़बग्घे, विविध पक्षी प्रजातियाँ, अरावली की विशिष्ट पारिस्थितिकी

आलोचकों का कहना है कि पिछले कई दशकों में इस क्षेत्र में बाघों की स्थायी उपस्थिति के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं। कुंभलगढ़ ने अपनी पारिस्थितिक पहचान मुख्यतः अन्य वन्यजीवों के साथ विकसित की है।

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है–

- क्या हर संरक्षित वन को टाइगर रिजर्व बनाना आवश्यक है?

भारत की संरक्षण सफलता केवल बाघों पर निर्भर नहीं है। उतना ही महत्वपूर्ण है उन पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण जो अनेक अन्य प्रजातियों को जीवन प्रदान करते हैं।

कॉरिडोर की समस्या

वन्यजीव विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है–संपर्क (कनेक्टिविटी), एक स्वस्थ बाघ आबादी के लिए विभिन्न वन क्षेत्रों के बीच प्राकृतिक आवागमन अत्यंत आवश्यक है।

जब बाघ आबादी अलग-थलग पड़ जाती है–

- अंतःप्रजनन (इनब्रीडिंग) बढ़ता है।
- आनुवंशिक विविधता घटती है।
- बीमारियों का जोखिम बढ़ता है।
- दीर्घकालिक अस्तित्व संकट में पड़ जाता है।

कई विशेषज्ञों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या कुंभलगढ़ के पास ऐसे मजबूत और सुरक्षित वन्यजीव गलियारे (वाइल्डलाइफ कॉरिडोर्स) हैं जो इसे अन्य प्रमुख बाघ क्षेत्रों से प्रभावी रूप से जोड़ सकें?

यदि नहीं, तो कुंभलगढ़ एक संरक्षण द्वीप बन सकता है–और ऐसे संरक्षण मॉडल लंबे समय तक अत्यधिक महंगे और चुनौतीपूर्ण सिद्ध होते हैं।

शिकार प्रजातियों की चुनौती

एक सरल सिद्धांत है– जहाँ पर्याप्त शिकार नहीं, वहाँ बाघ नहीं।

एक वयस्क बाघ को जीवित रहने के लिए बड़ी मात्रा में शिकार की आवश्यकता होती है। यद्यपि क्षेत्र में सांभर और नीलगाय की उपस्थिति दर्ज की गई है, फिर भी अनेक अध्ययनों ने शिकार आधार (प्रे-बेस) को और मजबूत करने की आवश्यकता बताई है।

यदि शिकार पर्याप्त नहीं होगा, तो संभावित परिणाम होंगे–

- बाघ पालतू पशुओं का शिकार करेंगे।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ेगा।
- स्थानीय लोगों में असंतोष पैदा होगा।
- संरक्षण प्रयासों के प्रति विरोध बढ़ेगा।

दुनिया भर के संरक्षण अनुभव बताते हैं कि पर्याप्त शिकार उपलब्ध कराए बिना शीर्ष शिकारी प्रजातियों को बसाना अक्सर संघर्ष का कारण बनता है।

मानवीय कीमत

इस बहस का सबसे संवेदनशील पहलू स्थानीय समुदायों से जुड़ा है। कुंभलगढ़ क्षेत्र में लंबे समय से भील, गरासिया, राइका और अन्य समुदाय रहते आए हैं, जिनका जीवन और आजीविका जंगल से गहराई से जुड़ी हुई है।

स्थानीय स्तर पर निम्नलिखित आशंकाएँ व्यक्त की गई हैं–

- चराई पर प्रतिबंध
- वन संसाधनों तक पहुँच में कमी
- संभावित विस्थापन का दबाव
- पारंपरिक जीवनशैली में हस्तक्षेप

यदि संरक्षण का बोझ केवल स्थानीय लोगों पर डाला जाएगा, तो संरक्षण की सफलता संदिग्ध हो जाएगी। किसी भी संरक्षण मॉडल की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय समुदाय स्वयं को उसका भागीदार महसूस करें, पीड़ित नहीं।

पर्यटन: कहीं यह आर्थिक झटका न बन जाए

कुंभलगढ़ केवल एक वन क्षेत्र नहीं है। यह एक विश्वप्रसिद्ध विरासत परिदृश्य है, जिसकी पहचान निम्नलिखित आधारों पर बनी है–

- कुंभलगढ़ दुर्ग
- ग्रामीण पर्यटन
- हेरिटेज होटल
- ट्रैकिंग मार्ग
- सांस्कृतिक पर्यटन
- स्थानीय अर्थव्यवस्था

टाइगर रिजर्व बनने के बाद अक्सर निम्न क्षेत्रों में कड़े नियमन लागू होते हैं–

- निर्माण गतिविधियाँ
- भूमि उपयोग
- व्यावसायिक विस्तार
- आधारभूत संरचना विकास

ऐसी स्थिति में यह गंभीरता से विचारणीय है कि क्या वर्तमान पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नुकसान पहुँच सकता है?

विडंबना यह होगी कि जो क्षेत्र पहले से ही विरासत पर्यटन के माध्यम से हजारों लोगों की आजीविका चला रहा है, उसे एक ऐसे प्रयोग के लिए सीमित कर दिया जाए जिसकी दीर्घकालिक सफलता अभी भी अनिश्चित है।

क्या यही संरक्षण निवेश की सर्वोत्तम दिशा है?

भारत के पास पहले से ही कई सफल बाघ परिदृश्य मौजूद हैं–

- रणथम्भौर नेशनल पार्क
- बांधवगढ़ नेशनल पार्क
- कान्हा नेशनल पार्क
- जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क

ऐसे में प्रश्न उठता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग कहाँ अधिक प्रभावी होगा–

- मौजूदा बाघ आवासों को मजबूत करने में?
- वन्यजीव कॉरिडोर विकसित करने में?
- तेंदुओं और अन्य प्रजातियों के संरक्षण में?
- अरावली पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने में?
- जल संरक्षण में?
- घासभूमियों के संरक्षण में?

यह बाघ-विरोधी तर्क नहीं है। यह संरक्षण की प्राथमिकताओं पर आधारित तर्क है।

लॉबिंग और हितों का प्रश्न

हर बड़े पर्यावरणीय प्रकल्प की तरह इस प्रस्ताव के पीछे भी विभिन्न हितधारक हैं। कुछ लोग निश्चित रूप से संरक्षण की भावना से इसका समर्थन करते हैं। लेकिन यह भी संभव है कि कुछ समूहों को इसमें दिखाई दें–

- अतिरिक्त वित्तीय संसाधन
- संस्थागत विस्तार
- शोध परियोजनाएँ
- प्रशासनिक प्रभाव
- संरक्षण ब्रांडिंग

ऐसी परिस्थितियाँ केवल कुंभलगढ़ तक सीमित नहीं हैं; दुनिया भर में बड़े संरक्षण प्रकल्पों के साथ ऐसा होता रहा है। इसीलिए आवश्यक है कि निर्णय वैज्ञानिक तथ्यों और स्वतंत्र मूल्यांकन पर आधारित हों, न कि केवल राजनीतिक उत्साह या भावनात्मक प्रतीकों पर।

- बाघों को विज्ञान चाहिए, भावनाएँ नहीं।
- क्या कुंभलगढ़ की सबसे बड़ी ताकत बाघ नहीं, कुछ और है?
- शायद इस पूरी बहस में सबसे कम चर्चा इसी संभावना की हुई है।
- कुंभलगढ़ को राष्ट्रीय महत्व प्राप्त करने के लिए बाघों की आवश्यकता नहीं है।

इसके पास पहले से ही है–

- अरावली की अद्वितीय पारिस्थितिकी
- अनुपम सांस्कृतिक विरासत
- तेंदुओं की सशक्त उपस्थिति
- भेड़िये और भालू
- स्थानीय एवं आदिवासी समुदाय
- ऐतिहासिक परिदृश्य
- भारत के सबसे प्रतिष्ठित दुर्गों में से एक, कुम्भलगढ़ फोर्ट

संभव है कि कुंभलगढ़ को एक ऐसे मॉडल के रूप में विकसित किया जाए जहाँ विरासत संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता एक साथ आगे बढ़ें। यह न केवल विशिष्ट होगा, बल्कि संभवतः अधिक टिकाऊ और व्यावहारिक भी।

निष्कर्ष

बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और विश्व संरक्षण इतिहास की सबसे प्रेरणादायक सफलताओं में से एक है। किन्तु सफल संरक्षण केवल उत्साह से नहीं, बल्कि कठिन प्रश्न पूछने के साहस से प्राप्त होता है।

यदि किसी परिदृश्य में पर्याप्त शिकार, मजबूत कॉरिडोर, पारिस्थितिक उपयुक्तता और स्थानीय सामाजिक स्वीकृति का अभाव है, तो वहाँ बाघों की पुनर्स्थापना अंततः बाघों और मनुष्यों–दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसलिए बहस को इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि–

क्या आप बाघों के पक्ष में हैं या विरोध में?

वास्तविक प्रश्न यह है–

बाघों के लिए, कुंभलगढ़ के लिए और उन लोगों के लिए क्या सबसे बेहतर है, जो पीढ़ियों से इस भूमि और जंगल के साथ जीवन जीते आए हैं? कभी-कभी संरक्षण का अर्थ किसी प्रजाति को पुनः बसाना होता है। और कभी-कभी संरक्षण का अर्थ यह स्वीकार करना होता है कि किसी भूभाग की सबसे बड़ी शक्ति उसी स्वरूप में निहित है, जैसा उसे प्रकृति ने स्वयं गढ़ा है।

ऑनलाइन छात्रवृत्ति घोटाले का पदार्फाश पश्चिम बंगाल से दो साइबर ठग गिरफ्तार

जयपुर @ पदमावत मीडिया। अजमेर पुलिस ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी छात्रवृत्ति राशि हड़पने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पश्चिम बंगाल से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में करीब 30 शिक्षण संस्थानों के नाम पर फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति प्राप्त कर सरकारी खजाने को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। मामले की जांच के लिए गठित विशेष टीम ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में कार्रवाई कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 85 सिम कार्ड, दो लैपटॉप, दो प्रिंटर, एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, सात एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक सहित कई डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। जांच में करीब 2100 बैंक खातों का डेटा, 1000 से अधिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड, 2000 आधार कार्ड एवं फोटो तथा 1500 से अधिक स्टाम्प दस्तावेजों की प्रतियां भी मिली हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरोह ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया का दुरुपयोग कर फर्जी दस्तावेजों और मोबाइल सिम के

माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेता था। गिरफ्तार आरोपी तबिबार रहमान और साहनामाज, निवासी उत्तर दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल) हैं। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों एवं संभावित साइबर धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही है।

नीट पुनर्परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थियों का बड़ा खुलासा: 30 लोग गिरफ्तार, मेडिकल छात्र और बायोमेट्रिक कर्मी भी शामिल

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

लखीसराय। बिहार में नीट (यूजी) 2026 पुनर्परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। लखीसराय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी परीक्षार्थियों, सहयोगियों और बायोमेट्रिक कर्मियों सहित कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वास्तविक अभ्यर्थियों की जगह डमी परीक्षार्थियों को परीक्षा दिलाने के लिए सुनियोजित साजिश रची गई थी, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया से जुड़े कर्मियों की भी संलिप्तता सामने आई है।

पुलिस के अनुसार 21 जून को लखीसराय जिले के चार परीक्षा केंद्रों पर नीट पुनर्परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान सूचना मिली कि कुछ केंद्रों पर वास्तविक अभ्यर्थियों के स्थान पर फर्जी अथवा डमी परीक्षार्थियों को बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जांच अभियान चलाया। जांच में तीन परीक्षा केंद्रों से फजीवाड़े का खुलासा हुआ और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र वास्तविक अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। इसके लिए फर्जी पहचान पत्र और कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग किया गया। पुलिस का दावा है कि पूरे नेटवर्क में बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया से जुड़े कुछ कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जिन्होंने डमी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिलाने में सहयोग किया।

गिरफ्तार फर्जी परीक्षार्थियों में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस छात्र, नर्सिंग छात्रा, आयुर्वेद चिकित्सा की छात्रा तथा अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी शामिल हैं। वहीं मामले में दो सहयोगियों और 18 बायोमेट्रिक कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध संबंधित थानों में अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट का संचालन कौन कर रहा था, इसके बदले कितनी रकम ली गई और राज्य के अन्य जिलों या परीक्षा केंद्रों में भी इसी प्रकार का नेटवर्क सक्रिय था या नहीं। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

खबर संक्षेप

72वीं रैंक के साथ आदित्य का रक्षा सेवा में चयन

उदयपुर @ पदमावत मीडिया। शहर के छात्र आदित्य प्रताप सिंह ने तकनीकी प्रवेश योजना (टीईएस) परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर

72वीं रैंक प्राप्त कर उदयपुर का नाम रोशन किया है। जेईई मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन और एसएसबी साक्षात्कार में सफलता के बाद उनका चयन सेना के प्रतिष्ठित संस्थान एमसीईएमई-55, सिकंदराबाद में हुआ है। आदित्य वहां चार वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर सेवाएं देंगे। उनके पिता भूपाल नोबल्स महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि माता राजकीय माध्यमिक विद्यालय मदार में व्याख्याता हैं। आदित्य की इस उपलब्धि पर परिवार, शिक्षकों एवं शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया।

शहरी सेवा शिविरों में 1,530 पट्टे जारी, आवेदनों के निस्तारण में तेजी

जयपुर @ पदमावत मीडिया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में आयोजित शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 12 से 22 जून तक आयोजित शिविरों में 1,530 पट्टे जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन के अनुसार शिविरों में 282 नामांतरण, 31 भवन निर्माण स्वीकृतियां, 81 उप-विभाजन एवं भूमि उपयोग परिवर्तन संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जबकि 166 फ्री होल्ड पट्टे भी जारी किए गए। इसके अलावा 2,191 जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए, 2,181 स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य, 1,053 जीवीपी हस्तांतरण तथा 1,246 फेरो कवर स्थापित किए गए। सड़कों, सीवरेज कनेक्शन एवं अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में भी प्रगति दर्ज की गई। जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशन में प्रशासनिक अधिकारी लगातार शिविरों की निगरानी कर रहे हैं, जिससे आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो रहा है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से शहरी सेवा शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

ग्रामीण सेवा शिविर में हाथों-हाथ हुआ समस्याओं का समाधान, विभिन्न योजनाओं का मिला लाभ

राजसमंद @ पदमावत मीडिया। ग्राम पंचायत सुखार में आयोजित ग्रामीण सेवा

शिविर में विभिन्न विभागों ने आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। राजस्व विभाग ने खातों के शुद्धिकरण, नामांतरण, सीमाज्ञान एवं राजस्व रिकॉर्ड संबंधी दर्जनों प्रकरणों का निस्तारण किया। पंचायत राज विभाग ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए तथा स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े कार्य संपादित किए। कृषि विभाग ने किसानों को मिनी किट वितरित किए और विभिन्न योजनाओं के आवेदन ऑनलाइन किए।

पशुपालन विभाग ने पशुओं का टीकाकरण, उपचार एवं मंगला पशु बीमा योजना के तहत पॉलिसियां जारी कीं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। सहकारिता विभाग ने किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया। ग्राम निवासी एजी हीमा के राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी त्रुटि का शिविर में ही निस्तारण किया गया। लगभग 20 वर्षों बाद रिकॉर्ड में नाम सही होने पर उन्होंने राज्य सरकार एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उपस्थित रहकर आमजन को सेवाएं प्रदान कीं।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त

उदयपुर @ पदमावत मीडिया। जिले में आगामी 23 से 26 जून तक छडी जुलूस, निर्जला एकादशी, छड़ी मिलन, मुहर्रम के उपलक्ष में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस हेतु जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने एक आदेश जारी कर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये हैं।

जिला आधारित विकास मॉडल से विकसित राजस्थान की नींव मजबूत होगी: मुख्यमंत्री

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में राजस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार जिला आधारित विकास मॉडल को प्राथमिकता देते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है, जिससे प्रत्येक जिले की विशेष पहचान, स्थानीय संसाधनों और आर्थिक संभावनाओं के अनुरूप विकास को नई गति मिल रही है।

मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर वी.के. सारस्वत की उपस्थिति में जिला घरेलू उत्पाद अनुमान विषय पर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले आधारित विकास की अवधारणा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग, निवेश और सुशासन आधारित नीतियों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हो रहा है और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र भी तेजी से विकसित हो रहा है। वर्तमान में छह हजार से अधिक सक्रिय स्टार्टअप युवाओं को रोजगार और नवाचार के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण पर गंभीरता से कार्य कर रही है। इससे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, पारंपरिक उत्पादों और जनजातीय क्षेत्रों में संचालित उद्यमों को संगठित अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का लाभ भी प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में पंच गौरव के अंतर्गत कृषि, उत्पाद, वन संपदा, खेल और पर्यटन क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिल रही है।

बैठक में प्रोफेसर वी.के. सारस्वत ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान उपलब्धियों का प्रदेश है। पेयजल, ग्रामीण विकास, पर्यटन, कृषि, खनन और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उच्च तकनीक आधारित डाटाबेस तैयार कर इन क्षेत्रों की आर्थिक क्षमता का और अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संतुलित और नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत आमजन के सुझावों और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर वर्ष 2030, 2035 और 2047 को ध्यान में रखते हुए विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति के सटीक मूल्यांकन के लिए मजबूत जिला घरेलू उत्पाद प्रणाली आवश्यक है। इसी दिशा में कृषि, पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, खनन और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में डेटा आधारित विकास मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर विकास की निगरानी और मूल्यांकन के लिए डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण संभव हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आज देश के अग्रणी अक्षय ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल है। हरित ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे निवेश और नवाचार राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के साथ-साथ सतत विकास के लक्ष्यों को भी मजबूत कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल विजन को साकार करते हुए प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विशेषताओं, स्थानीय आवश्यकताओं और संभावनाओं के आधार पर आकांक्षी उपखंडों का समग्र विकास किया जा रहा है। प्रमुख फसलों और उत्पादों की पहचान कर उनके प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन की प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिससे लघु, कुटीर और पारंपरिक उद्योगों को मजबूती मिलने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल रहा है।

बैठक में राजस्थान की प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देने, राज्य के आर्थिक परिदृश्य तथा मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान से संबंधित प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी संभागीय आयुक्त और कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

बिहार पुलिस का बड़ा अभियान:

एक माह में 10,513 अपराधी गिरफ्तार, 35,677 आरोपी दबोचे गए

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

पटना। बिहार पुलिस ने 16 मई से 20 जून 2026 तक राज्यभर में चलाए गए विशेष अपराध नियंत्रण अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,513 गंभीर अपराधों में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस अवधि में हत्या, डकैती, लूट, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में कार्रवाई तेज करते हुए अपराधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान हत्या के 724, डकैती के 106, लूट के 256 तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार से जुड़े 381 मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 10,513 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं राज्यभर में कुल 35,677 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने अपराधियों की संपत्ति जब्ती के तहत चार मामलों में कार्रवाई कर न्यायालय में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 1,16,042 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि 25,284 लोगों से शांति एवं बंध पत्र भरवाए गए। पुलिस मुख्यालय के अनुसार मई 2026 के दौरान राज्य की विभिन्न अदालतों में 12,166 मामलों में सुनवाई पूरी हुई, जिनमें 16,136 व्यक्तियों को सजा सुनाई गई। इनमें 100 लोगों को आजीवन कारावास, 44 को 10 वर्ष से अधिक तथा 143 को 10 वर्ष तक की सजा सुनाई गई। इसके अलावा हजारों दोषियों पर जुमार्ना भी लगाया गया। विशेष अपराध नियंत्रण अभियान के दौरान 387 अवैध हथियार, 1,356 कारतूस, 10 बम, चार डेटोनेटर और पांच अवैध हथियार निर्माण इकाइयों का खुलासा किया गया। साथ ही 12.859 किलोग्राम हेरोइन, 6,056 किलोग्राम गांजा तथा बड़ी मात्रा में अन्य मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने 1,972 वाहनों को भी जब्त किया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बताया कि आगामी पर्व-त्योहारों को देखते हुए सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यभर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष निगरानी जारी रहेगी।

ग्रामीण सेवा शिविर बना अधिकारों का आधार, 6 परिवारों को मिले आवासीय भूखंडों के पट्टे

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

सलूम्बर । ग्रामीण सेवा शिविर-2026 ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। ग्राम पंचायत लांबीडूंगरी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में वर्षों से आवासीय भूखंडों के वैध पट्टों की प्रतीक्षा कर रहे छह पात्र परिवारों को मौके पर ही पट्टे वितरित कर बड़ी राहत प्रदान की गई। शिविर में प्राप्त आवेदनों के आधार पर भूमि एवं पात्रता संबंधी दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया गया। आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार आवासीय भूखंडों के पट्टे जारी किए गए। इससे लंबे समय से लंबित भूमि अधिकारों का समाधान संभव हो सका। शिविर के माध्यम से सोमा, रतना, गौतम, कमला, नाथूलाल एवं रोडी को आवासीय भूखंडों के पट्टे प्रदान किए गए। पट्टा मिलने से इन परिवारों के भूमि संबंधी अधिकार सुरक्षित हुए हैं तथा अब वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के साथ-साथ आवास एवं अन्य विकासात्मक सुविधाओं के लिए भी पात्र हो सकेंगे। पट्टा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों से लंबित समस्या का समाधान एक ही शिविर में हो गया। उन्होंने राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस पहल से आमजन का प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। प्रभारी सचिव खजान सिंह ने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविरों का उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को आमजन से जुड़े प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए।

झाब जैन परिषद द्वारा योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

संवाददाता : माणकमल भंडारी

भीनमाल/ मुंबई । झाब जैन परिषद द्वारा माधव बाग हॉल सी पी टैंक मुम्बई परिसर में योगा का कार्यक्रम आयोजित किया गया । जिसमें झाब नगर के अनेक युवा और बुजर्गों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया । मीडिया प्रभारी माणकमल भंडारी ने बताया कि कार्यक्रम के प्रायोजक घेवरचंद गुणेशमल अंगारा रहे । परिषद के संस्थापक अध्यक्ष खीमराज जैन ने कहा कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि बेहतर जीवन जीने की कला है । योग सिर्फ शरीर को मोड़ता नहीं बल्कि बेहतर राह पर जीवन को जोड़ता भी है । प्रायोजक घेवरचंद अंगारा ने कहा कि स्वस्त शरीर और शांत मन का सबसे सरल मार्ग है योग । अध्यक्ष नरेश भंडारी ने प्रायोजक परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास नहीं बल्कि मन को शांत, विचारों को सकारात्मक और जीवन को संतुलित बनाने की श्रेष्ठ कला है । उन्होंने ग्रामवासियों से आग्रह किया की योग को केवल एक दिन का कार्यक्रम ना बनाकर इसे अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाये। अध्यक्ष भंडारी ने नारा दिया की स्वस्थ रहेगा इंसान , तभी बनेगा सशक्त हमारा हिंदुस्थान । परिषद के पूर्व अध्यक्ष अरविंद मुनोत, कार्यकारी उपाध्यक्ष संजय श्रीश्रीमाल, उपाध्यक्ष उत्तम गोटी, विक्रम मुनोत, कोषाध्यक्ष विमल गांधी, सह कोषाध्यक्ष तरुण संघवी, सचिव रमेश वेदमुथा, सह सचिव जयंती भंडारी, पूर्व अध्यक्ष उत्तम भंसाली, सांवलचंद गांधी, जबरमल शाह, दीपचंद वेदमुथा, छबील अदानी, जबरमल मुनोत, दिनेश मुनोत, सायर वेदमुथा, अशोक भंडारी, भरत हरणफाल, महेंद्र भंसाली, महेंद्र मुथा, जितेंद्र वीरवाडीया, सुरेश फोलामुथा, बाबूलाल श्रीश्रीश्रीमाल के साथ प्रायोजक परिवार के घेवरचंद अंगारा, प्रवीण अंगारा, जितेन्द्र अंगारा एवं विदान अंगारा उपस्थित रहे । मंच संचालन महेंद्र भंसाली द्वारा किया गया । सचिव रमेश वेदमुथा द्वारा सभी ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया।

नशा मुक्ति का दिलाया संकल्प, महिला अधिकारों के प्रति किया जागरूक

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

उदयपुर। ग्राम पंचायत नाई में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त सहयोग से जतन संस्थान द्वारा संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, पुलिस थाना नाई की ओर से जागरूकता एवं परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में विधिक परामर्शदाता अनिता प्रजापत ने ग्रामीणों एवं महिलाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए नशे से होने वाले सामाजिक, पारिवारिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों की जानकारी दी तथा नशा मुक्त समाज निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

अनिता प्रजापत ने महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम, सखी वन स्टॉप सेंटर, नारी निकेतन तथा महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र में आने वाले पारिवारिक विवादों में आपसी समझाइश के माध्यम से समाधान का प्रयास किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता और न्यायालयीन मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों, सहायता योजनाओं एवं हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी देते हुए किसी भी प्रकार की समस्या होने पर बेझिझक महिला सुरक्षा केंद्र से संपर्क करने का आग्रह किया।

शिविर के दौरान महिलाओं की समस्याएं भी सुनी गईं। एक महिला के प्रकरण का मौके पर निस्तारण करते हुए आवश्यक राहत प्रदान की गई तथा आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण दर्ज किया गया। इससे महिलाओं में केंद्र के प्रति विश्वास और जागरूकता बढ़ी।

महिला अधिकारिता विभाग की पर्यवेक्षक पूजा पाटीदार ने बाल विवाह रोकथाम को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि बाल विवाह सामाजिक बुराई है, जिसे समाज की सहभागिता से ही समाप्त किया जा सकता है। वहीं साथीन अर्चना मेघवाल ने काली बाई भील महिला सम्बल उड़ान योजना की जानकारी देकर पात्र महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं पंचायत के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी समस्याएं साझा कीं तथा विभागीय योजनाओं एवं महिला सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं। कार्यक्रम ने महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति एवं सामाजिक जागरूकता का प्रभावी संदेश दिया।

आदर्श विद्या मंदिर के नवीन भवन का शिलान्यास मंगलवार को

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

संवाददाता : माणकमल भंडारी

भीनमाल । कुसुमदेवी भूरसिंह राव बोरली आदर्श विद्या मंदिर सुथड़ी के नवीन विद्यालय भवन का भव्य शिलान्यास मंगलवार को होने जा रहा है। यह आयोजन न केवल एक भवन निर्माण का शुभारंभ है, बल्कि क्षेत्र में शिक्षा, संस्कार और सामाजिक विकास के नए युग की शुरूआत भी माना जा रहा है।

वंचित विद्यार्थियों के लिए नई आशा

इस विद्यालय का निर्माण विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। लंबे समय से क्षेत्र में एक आदर्श शिक्षण संस्थान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे अब यह नया भवन पूरा करेगा। यह विद्यालय आने वाले समय में जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का सशक्त केंद्र बनेगा। आयोजन समिति के अनुसार कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रातः 8 बजे विधिवत भूमि पूजन किया जाएगा, जिसके बाद सुबह 10 बजे ग्राम सुंथड़ी में मुख्य समारोह आयोजित होगा।जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, शिक्षाविद्, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिकों के उपस्थित रहने की संभावना है।

विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस अवसर पर गुरु कृपा आश्रम जोधपुर के संत कृपाराम महाराज अपनी दिव्य उपस्थिति से कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद एवं भाजपा हरियाणा प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया, मंत्री जोराराम कुमावत, सांसद लुंबाराम चौधरी, विधायक पूर्व विधायक कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त भाजपा के सैकडों कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के प्रबुद्धजन, समाजसेवी और सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी।

आदर्श विद्या मंदिर केवल शिक्षा प्रदान करने का केंद्र ही नहीं होगा, बल्कि विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति के संस्कार विकसित करने का भी माध्यम बनेगा। यहां से निकलने वाले विद्यार्थी न केवल शैक्षणिक रूप से सक्षम होंगे, बल्कि समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी अपनी पहचान बनाएंगे।

क्षेत्र के विकास की ओर मजबूत कदम

यह नया विद्यालय भवन क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। आयोजन समिति का मानना है कि यह पहल आने वाले समय में ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने और समाज के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

खबर संक्षेप

क्रिकेट कप सीरीज-2 में पी मार्ट बनी विजेता, हीरोज 11 रही उपविजेता

उदयपुर @ पदमावत मीडिया। जैन युवा मित्र संस्थान एवं दिवाकर किंग्स के तत्वावधान में विराट स्पोर्ट्स अरेना, सेक्टर-8

में आयोजित क्रिकेट कप सीरीज-2 का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। प्रतियोगिता में पी मार्ट की टीम विजेता तथा हीरोज 11 की टीम उपविजेता रही। विनोद कोठारी ने बताया कि प्रतियोगिता में रौनक सेठ को मैन ऑफ द सीरीज, हर्ष जारोली को बेस्ट बैट्समैन और प्रियांश चित्तौड़ा को बेस्ट बॉलर का पुरस्कार प्रदान किया गया। टूर्नामेंट की विशेषता प्रत्येक डॉट बॉल पर एक पौधा लगाने का संकल्प रहा, जिसके तहत संस्था ने 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। संस्थान अध्यक्ष पवन मेहता ने सभी प्रतिभागियों एवं सहयोगियों का आभार जताया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में संयोजक सुशील दाणी, अंकित नलवाया तथा सह-संयोजक हितेश नागोरी और आशीष दाणी का विशेष योगदान रहा। प्रतियोगिता में जैन समाज की 23 टीमों ने भाग लिया।

आज विभिन्न स्थानों पर होंगे शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर

सलूम्बर @ पदमावत मीडिया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में संचालित शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के तहत मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आमजन को विभिन्न विभागीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। शहरी सेवा शिविर नगर परिषद सभागार में वार्ड संख्या 7 एवं 8 के लिए आयोजित होगा। वहीं ग्रामीण सेवा शिविर गींगला, निम्बोदा, नेवातलाई, भोराई, कलात एवं ओवरा ग्राम पंचायतों में लगाए जाएंगे। शिविरों में राजस्व, पंचायतीराज, कृषि, जलदाय, विद्युत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, शिक्षा तथा पशुपालन विभाग सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। यहां पात्र लाभार्थियों का पंजीयन, प्रमाण-पत्र जारी करने, शिकायतों के निस्तारण तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिला प्रशासन ने आमजन से अधिकाधिक संख्या में शिविरों में पहुंचकर सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने की अपील की है।

ठगी में इस्तेमाल बैंक खाते का धारक गिरफ्तार, खाते में आए थे 7 .79 लाख रुपये

उदयपुर @ पदमावत मीडिया। साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ठगी की राशि के लेन-देन में इस्तेमाल किए गए बैंक खाते के धारक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने बैंक खाते और उससे संबंधित बैंकिंग सुविधाएं कमीशन के बदले अन्य लोगों को उपलब्ध कराता था, जिनका उपयोग साइबर अपराधों में किया जा रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा के सुपरविजन में साइबर थाना प्रभारी विनय चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। साइबर थाना में दर्ज प्रकरण संख्या 05/2026 की जांच के दौरान साइबर ठगी में प्रयुक्त बैंक खाते की जानकारी सामने आई थी। जांच में पता चला कि मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के सेमलिया निवासी दीपेन्द्र सिंह ने अपने नाम से बैंक खाता खुलवाकर उससे संबंधित एटीएम कार्ड, चेकबुक, नेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड कमीशन के बदले अन्य व्यक्तियों को दे रखे थे। उक्त खाते का उपयोग साइबर ठगी की राशि प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी के बैंक खाते में साइबर ठगी से संबंधित लगभग 7 लाख 79 हजार 871 रुपये की राशि जमा की गई थी। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका और ठगी की पूरी श्रृंखला का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार साइबर अपराधियों द्वारा भोले-भाले लोगों के बैंक खातों का उपयोग कर ठगी की रकम को विभिन्न खातों में स्थानांतरित किया जाता है। ऐसे मामलों में बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति भी अपराध में सहभागी माने जाते हैं और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। मामले में विस्तृत अनुसंधान जारी है। इस कार्रवाई में पुलिस उप अधीक्षक एवं साइबर थाना प्रभारी विनय चौधरी, उप निरीक्षक सुखदेव सिंह, कांस्टेबल आलोक, कांस्टेबल अनिल पुनिया तथा कांस्टेबल रामानंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सांगानेर थाने पहुंचे पुलिस महानिदेशक 15 दिन में दिखे परिणाम, फिर होगी समीक्षा

गोद लिए थाने का किया निरीक्षण, उत्कृष्ट थाना बनाने के दिए निर्देश

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

जयपुर । पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सोमवार को अपने गोद लिए सांगानेर पुलिस थाने का निरीक्षण कर थाने की कार्यप्रणाली, रिकॉर्ड संधारण, लंबित प्रकरणों, अपराध अनुसंधान एवं पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी उत्कृष्ट थाना मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्यों को गति देते हुए सांगानेर थाने को आदर्श थाना बनाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाएं।

निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिदेशक ने थाना रिकॉर्ड, अपराध अनुसंधान, प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा आधारभूत सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने महत्वपूर्ण अभिलेखों के बेहतर संधारण तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक कार्य का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया जाए और कार्यप्रणाली को निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए। राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि प्रकरणों के निस्तारण में गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके। उन्होंने पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित विभिन्न अभियानों एवं प्राथमिकता वाले कार्यों को थाना स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। गंभीर अपराधों, वारंट निष्पादन, निरोधात्मक कार्रवाई, सड़क सुरक्षा तथा नागरिक सेवाओं से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा।

उन्होंने जनसुनवाई व्यवस्था को और अधिक संवेदनशील एवं प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी ने थाने की कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की।

पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट कहा कि थाना स्तर पर वास्तविक और दिखाई देने वाले सुधार होने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिन के भीतर निर्धारित कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए और कहा कि वे स्वयं पुनः थाने का दौरा कर निदेशों की पालना एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

उल्लेखनीय है कि डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस-2025 में लिए गए निर्णयों के तहत प्रदेश के 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाले आईपीएस अधिकारियों को एक-एक पुलिस थाना गोद सौंपा गया है। इन अधिकारियों को अपराध नियंत्रण, अनुसंधान की गुणवत्ता, लंबित मामलों के निस्तारण, वारंट निष्पादन, सड़क सुरक्षा एवं जनसेवा संबंधी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। विशेष बात यह है कि पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने अपने पुलिस सेवा जीवन की शुरूआत भी सांगानेर थाने से ही की थी। निरीक्षण के दौरान डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों पर होगी कार्रवाई, सेवा शिविरों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: जिला कलेक्टर

समयबद्ध समाधान और बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

सलूम्बर । जिला कलेक्टर मुहम्मद जुनैद पी.पी. ने जिले में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और विकास कार्यों की प्रगति को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने संपर्क पोर्टल, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की प्रगति की विभागवार समीक्षा करते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

बैठक में जिला कलेक्टर ने अग्रणी बैंक अधिकारी को युवा संबल योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विशेष शिविर आयोजित करने तथा उद्योग विभाग के समन्वय से अधिकाधिक युवाओं को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोजगार एवं स्वरोजगार योजनाओं का लाभ पात्र युवाओं तक प्रभावी रूप से पहुंचना चाहिए। संपर्क पोर्टल की समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन की परिवेदनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि 14 दिन से अधिक अवधि से लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय पर शिविरों में उपस्थित रहकर आमजन को त्वरित एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवा शिविरों का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करना है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी पूर्ण गंभीरता और जवाबदेही के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाए।

ई-गवर्नेंस की समीक्षा में महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा चिकित्सा विभाग को मोबाइल एप्लीकेशन संचालन में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए, ताकि ऑनलाइन सेवाओं का संचालन निर्बाध रूप से जारी रह सके।

बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने नगर परिषद को वेस्ट टू वेल्थ पार्क परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने तथा सहकारिता विभाग को उपभोक्ता भंडार के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि समर कंटीजेंसी योजना के तहत जिले में कहीं भी पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग एवं शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने विभागवार प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए तथा सभी अधिकारियों से जनहित से जुड़े कार्यों में संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

40 साल पुराना भूमि विवाद सुलझा

ग्रामीण सेवा शिविर बना दो बहनों की खुशियों का आधार

सलूम्बर @ पदमावत मीडिया। ग्रामीण सेवा शिविर-2026 आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच बनकर सामने आ रहा है। ग्राम पंचायत श्यामपुरा, तहसील सेमारी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में लगभग 40 वर्षों से लंबित भूमि विवाद का समाधान कर प्रशासन ने दो परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की।

ग्राम जोधपुरिया निवासी सगी बहनों हीराबाई एवं धुलीबाई के बीच वर्षों से भूमि बंटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा था। यह मामला लंबे समय से लंबित था, जिससे दोनों परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीण सेवा शिविर में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने दोनों पक्षों की विस्तार से सुनवाई कर समझाइश की, जिसके बाद दोनों बहनों ने आपसी सहमति से भूमि बंटवारे पर सहमति व्यक्त की।

इसके पश्चात राजस्व अधिकारियों ने नियमानुसार भूमि का बंटवारा तैयार कर आवश्यक राजस्व अभिलेखों में कार्यवाही पूर्ण की तथा बंटवारा फेहरिस्त तैयार की। प्रभारी सचिव खजान सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. दिनेश राय सापेला, उपखंड अधिकारी सर्वेश्वर निम्बार्क एवं तहसीलदार की उपस्थिति में दोनों बहनों को बंटवारा आदेश की प्रति एवं बंटवारा फेहरिस्त सौंप दी गई।

चार दशक पुराने विवाद के समाधान के बाद दोनों परिवारों में खुशी का माहौल देखने को मिला। लाभार्थियों ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर उनके लिए राहत और न्याय का माध्यम बनकर आया है।

ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान राजस्व विभाग द्वारा कुल 8 आपसी सहमति से बंटवारे संपादित किए गए। इनमें 40 वर्षों से लंबित इस भूमि विवाद का समाधान विशेष उपलब्धि के रूप में सामने आया। यह सफलता प्रशासन की संवेदनशील कार्यशैली, पारदर्शी व्यवस्था और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से वर्षों पुराने विवादों एवं लंबित प्रकरणों का मौके पर समाधान कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई जा रही है। इससे न केवल आमजन का प्रशासन पर विश्वास मजबूत हो रहा है, बल्कि गांवों में सामाजिक समरसता, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण भी सुदृढ़ हो रहा है।

58 साल का इंतजार खत्म: मगरा स्कूल को आखिरकार मिला भूमि का पट्टा

उदयपुर @ पदमावत मीडिया। पंचायत समिति खेरवाड़ा अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मगरा के इतिहास में वर्ष 2026 मील का पत्थर साबित हुआ है। वर्ष 1968 में स्थापित हुए इस विद्यालय के पास पिछले 58 वर्षों से अपनी भूमि का वैध पट्टा मौजूद नहीं था। लेकिन अब, करीब छह दशकों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है और विद्यालय को भवन निर्माण हेतु भूमि का पट्टा आधिकारिक रूप से प्राप्त हो गया है। यह ऐतिहासिक सफलता ग्राम पंचायत मगरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान मिली। शिविर में अधिकारियों की संवेदनशीलता और तत्परता के चलते दशकों से अटका यह मामला चंद दिनों में सुलझा लिया गया। इस पुनीत कार्य में विकास अधिकारी मदनलाल लोहार, तहसीलदार रेवत राम, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खेरवाड़ा ज्योति प्रकाश पटेल एवं प्रशासक उर्मिला देवी ने व्यक्तिगत रुचि ली। इन सभी अधिकारियों और प्रशासनिक अमले के अथक प्रयासों व आपसी समन्वय से विद्यालय को उसकी भूमि का मालिकाना हक मिल सका। पट्टा न होने के कारण पिछले कई सालों से विद्यालय के नए भवन निर्माण और बुनियादी ढाँचे के विकास में तकनीकी व कानूनी अड़चनें आ रही थीं। अब पट्टा मिलने के बाद विद्यालय के भव्य और सुविधायुक्त भवन निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

ग्रामीण सेवा शिविर बना दिव्यांगजनों का सहारा, मौके पर मिला पेंशन योजना का लाभ

विकलांगता प्रमाण पत्र जारी कर कराया वार्षिक सत्यापन, पात्र हितग्राहियों को मिली बड़ी राहत

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

सलूम्बर । ग्रामीण सेवा शिविर-2026 आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच बनकर सामने आ रहा है। ग्राम पंचायत सेमाल में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में दिव्यांगजनों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़कर बड़ी राहत प्रदान की गई। शिविर के दौरान विकलांगता प्रमाण पत्र के अभाव में पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे लाभार्थियों के प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। लाभार्थी प्रकाश चन्द्र मेघवाल एवं कला कुमारी के विकलांगता प्रमाण पत्र जारी कर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराई गईं तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए वार्षिक सत्यापन भी कराया गया। इसके साथ ही दोनों

हितग्राहियों को पेंशन योजना का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया। ग्रामीण सेवा शिविर में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने समन्वित प्रयास करते हुए प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया, जिससे लाभार्थियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली। पेंशन योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का आभार जताया। शिविर प्रभारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति जयसमंद दयाचंद यादव के निर्देशन तथा सहायक शिविर प्रभारी नायब तहसीलदार तुलसीराम मीणा के समन्वय में यह कार्रवाई संपन्न हुई। शिविर में बीसीएमओ डॉ. मनीष पाठक, सीडीपीओ प्रकाश चौबीसा, सीबीईओ प्रीति शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

ग्रामीण सेवा शिविरों का उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ उनके गांव में ही उपलब्ध कराना है। दिव्यांगजनों को समय पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की यह पहल सरकार की संवेदनशील एवं जनकल्याणकारी सोच का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आई है।

राज्य सरकार के सतत प्रयासों से देवास तृतीय एवं देवास-चतुर्थ को मिली वन स्वीकृति

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

उदयपुर। उदयपुर शहर की महत्वाकांक्षी देवास तृतीय एवं देवास चतुर्थ पेयजल परियोजना को वन स्वीकृति प्राप्त होने से परियोजना के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह उपलब्धि राज्य सरकार के सतत प्रयासों, प्रभावी समन्वय एवं सभी संबंधित विभागों के निरंतर सहयोग का परिणाम है, जिससे उदयपुर की लाइफलाइन मानी जाने वाली इस परियोजना के निर्माण कार्यों को अब और अधिक गति मिलेगी। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान सरकार, राजस्थान वन विभाग तथा परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति जल संसाधन विभाग ने हार्दिक आभार व्यक्त किया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 25 अप्रैल 2023 को 1690.55 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। परियोजना के तहत गोगुंदा क्षेत्र में देवास-तृतीय एवं देवास-चतुर्थ के तहत बांधों तथा लंबी सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, जिनके माध्यम से जल का संचयन एवं उदयपुर की झीलों तक आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कार्यों में प्रगति

प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। 2349 प्रभावित किसानों में से 812 किसानों को 20.73 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है।प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए भूमि आरक्षित कर आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही जारी है।

निर्माण कार्यों को मिलेगी रफ्तार

परियोजना के बांध एवं सुरंग निर्माण कार्यों के लिए ठेके जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न स्थलों पर निर्माण गतिविधियां प्रगति पर हैं। वन स्वीकृति मिलने से शेष प्रक्रियाओं को भी तेजी मिलेगी और परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन का मार्ग और अधिक सुगम होगा।

इनका रहा महत्वपूर्ण योगदान

वन स्वीकृति प्राप्त होने पर जल संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान सरकार, वन विभाग तथा परियोजना से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

उदयपुर के भविष्य के लिए मील का पत्थर

विशेषज्ञों के अनुसार देवास-तृतीय एवं देवास-चतुर्थ परियोजना उदयपुर की बढ़ती आबादी, पर्यटन गतिविधियों और भविष्य की जल मांग को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना पूर्ण होने के बाद शहर को दीर्घकालिक जल सुरक्षा मिलेगी और यह योजना उदयपुर के विकास की आधारभूत जरूरतों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।

खबर संक्षेप

अनुसूचित जाति वर्ग के हितों से जुड़ी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाएं : श्री नायक

उदयपुर @ पदमावत मीडिया। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार नायक ने सोमवार को उदयपुर पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री नायक ने राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम (अनुजा निगम) के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं एवं योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने तथा अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।

आयोग अध्यक्ष ने कौशल विकास एवं आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षित अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने पर विशेष बल दिया। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से संचालित विभिन्न वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ ऐसे प्रशिक्षित युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें रोजगार एवं आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर मिल सकें। श्री नायक ने उद्योग विभाग की दलित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को सभी प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) दीपेंद्र सिंह राठौड़, अनुजा निगम की परियोजना प्रबंधक रजनी मालीवाड़, सहायक प्रबंधक वीना मेहरचंदानी, जिला उद्योग अधिकारी चोखाराम, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) के ललित कुमार, समाजसेवी गजपाल सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन

उदयपुर @ पदमावत मीडिया। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेते हुए जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की प्रगति का फीडबैक लिया। बैठक में कलेक्टर अग्रवाल द्वारा संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों, अंतरविभागीय मामलों के निस्तारण, सतर्कता समिति एवं जिला स्तरीय जनसुनवाई से संबंधित प्रकरणों तथा दिशा बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए निदेर्शों एवं सुझावों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर अग्रवाल ने विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित अंतरविभागीय प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि समन्वय के अभाव में किसी भी मामले को लंबित नहीं रखा जाए। उन्होंने समीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऐसे मामलों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सतर्कता समिति तथा जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से प्रकरणवार प्रगति की जानकारी लेते हुए लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। जिला कलेक्टर ने गत दिनों मे आयोजित दिशा बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों एवं निदेर्शों के अनुपालना की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दे आमजन की अपेक्षाओं से जुड़े होते हैं, इसलिए इन पर विशेष प्राथमिकता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

7 वर्ष की उम्र में उठा पिता का साया, माँ ने धागा फैक्ट्री में मेहनत कर लाल को बनाया फौजी

अग्निवीर कुलदीप सिंह राठौड़ का खेरोदा में ऐतिहासिक स्वागत

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

उदयपुर। जिले के खेरोदा कस्बे के वीर सपूत कुलदीप सिंह राठौड़ भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में 6 माह की कठिन ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर सोमवार को अपने गृह नगर खेरोदा लौटे। देश सेवा का गौरवपूर्ण संकल्प लेकर लौटे वीर जवान का पूरे गांव ने पलक-पावड़े बिछाकर ऐतिहासिक और भव्य स्वागत किया। कुलदीप के महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में स्थित आर्म्ड क्रॉप्स सेंटर एंड स्कूल में 24 सप्ताह की कठोर ट्रेनिंग पूर्ण कर पैतृक गांव खेरोदा पहुंचने को लेकर पूरे क्षेत्र में सुबह से ही अपूर्व उत्साह, उमंग और देशभक्ति का माहौल देखा गया। गांव की सीमा पर पहुंचते ही ग्रामीणों और युवाओं ने भारत माता के जयकारों के साथ कुलदीप की अगवानी की। इसके बाद पूरे कस्बे में डीजे साउंड की धुनों और देशभक्ति गीतों के साथ एक विशाल जुलूस निकाला गया, जहाँ ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर और साफा पहनाकर अपने लाडले का अभिनंदन किया। इस दौरान कुलदीप सिंह ने कस्बे के प्रमुख धार्मिक स्थलों - माताजी मंदिर, चारभुजा नाथ मंदिर और कल्लाजी राठौड़ मंदिर पहुंचकर शीश नवाया और देश सेवा का आशीर्वाद लिया। राजपूत समाज के चारभुजानाथ मंदिर परिसर में परिवारजनों, समाजजनों और ग्रामीणों द्वारा अग्निवीर कुलदीप को केले से तोला गया। इस पावन अवसर पर युवाओं को सेना भर्ती के लिए प्रेरित करने वाली मेवाड़ डिफेंस अकादमी नवानीया द्वारा भी कुलदीप का भव्य स्वागत और बहुमान किया गया, तथा उनकी इस उपलब्धि को क्षेत्र के युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्त्रोत बताया।

कुलदीप सिंह राठौड़ का सफलता तक का यह सफर अत्यंत प्रेरणादायक और भावुक कर देने वाला रहा है। वर्ष 2011 में जब कुलदीप मात्र 7 वर्ष के थे, तब उनके पिता स्व. बहादुर सिंह राठौड़ का आकस्मिक देहांत हो गया था। ऐसी विकट एवं कठिन परिस्थितियों में भी उनकी माता लाड़ कुंवर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उदयपुर की एक धागा फैक्ट्री में श्रमिक के रूप में अत्यंत कठिन परिश्रम और मजदूरी करते हुए अपने पुत्र को बड़ा किया और उसके देश सेवा के सपने को साकार करने के लिए अग्निवीर की तैयारी करवाई। कुलदीप सिंह ने बताया कि आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव में करने के बाद शारीरिक शिक्षक गोपाल मेहता मेनारिया के मार्गदर्शन व प्रेरणा व सहयोग से 9 वीं से 11वीं तक की पढ़ाई कानोड़ के वर्धमान हॉस्टल में रहकर जवाहर विद्यापीठ से पूरी की, 12 उत्तीर्ण करने के बाद द्रोणाचार्य कॉलेज भिंडर से बी ए प्रथम वर्ष में एनसीसी में ए प्रमाण पत्र हासिल किया जहां से सेना में जाने का निर्णय लिया। शारीरिक शिक्षक गोपाल मेहता ने हर मुश्किल वक्त में साथ व मोटिवेशन दिया, 2022 से निरंतर सेना भर्ती की तैयारी करता रहा। नवानिया स्थित मेवाड़ डिफेंस एकेडमी में सेना भर्ती का 4 माह का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। अग्निवीर की परीक्षा में प्रथम प्रयास में असफल रहने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी फिर से कठोर परिश्रम किया। आखिरकार माँ-बेटे की बरसों की तपस्या रंग लाई और कुलदीप सेना में चयनित होकर लौटे। इस भव्य समारोह के दौरान भारी संख्या में प्रबुद्धजन, ग्रामीण, युवा और मातृशक्ति उपस्थित रही।

कल्लाजी राठौड़ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कुलदीप ने मार्च पास्ट करते हुए मां को सेल्यूट किया और अपनी सेना की कैप मां के सिर पर रख गले लग गया। इस दृश्य ने उपस्थित जन समूह को भावुक कर दिया।

सेना ने कुलदीप की मां को गौरव पदक से किया सम्मानित

सेना द्वारा कुलदीप सिंह की मां लाडकुंवर को गौरव पदक भेज कर सम्मानित किया जिसमें मेरी संतान देश को समर्पित अंकित है। कुलदीप ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान हुये समस्त फिजिकल टेस्ट में उसने एक्सीलेंस रैंक हासिल की और सेना के टैंक 90 टैंक को चलाने का बेसिक एवं एडवांस प्रशिक्षण प्राप्त किया। कुलदीप ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद उसकी प्रथम नियुक्ति 20 लाऊंसर यूनिट बबीना (उत्तर प्रदेश) में की गई है 4 जुलाई वहां रिपोर्ट करेंगे।

सफलता की कहानी : ईसवाल में खेल स्टेडियम निर्माण की राह प्रशस्त

अड़चन बने रास्ते की हाथों-हाथ संशोधित तरमीम जारी

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

उदयपुर। बड़गांव उपखण्ड की ग्राम पंचायत ईसवाल में आयोजित ग्राम सेवा शिविर ग्रामवासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईसवाल के खेल स्टेडियम निर्माण की राह में बरसों की आ रही बाधा का हाथों हाथ समाधान किया गया।

यह है मामला

राउमावि ईसवाल में खेल मैदान हेतु वर्ष 2012 में 0.8000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। हाल ही में डीएमएफटी योजना के तहत इस खेल मैदान पर खेल स्टेडियम निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत हुआ। किन्तु खेल मैदान के लिए आवंटित 0.8000 हेक्टेयर भूमि पर्याप्त नहीं होने के कारण स्वीकृत बजट का पूर्ण उपयोग संभव नहीं हो पा रहा था।खेल मैदान के समीप स्थित 0.4600 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि

को खेल स्टेडियम में शामिल करने में एक बड़ी प्रशासनिक अड़चन सामने आ रही थी। समस्या यह थी कि वर्तमान आवंटित 0.8000 हेक्टेयर भूमि और समीप स्थित 0.4600 हेक्टेयर बिला नाम भूमि के मध्य राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में एक रास्ता दर्ज था। इस कारण अतिरिक्त भूमि का मौजूदा खेल मैदान से एकीकरण कर एकचक खेल स्टेडियम बनाना संभव नहीं हो पा रहा था, जिससे योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाता।

शिविर में हुआ समाधान, निखरेंगी खेल प्रतिभाएं

समस्या के समाधान हेतु ग्रामवासियों ने ग्राम सेवा शिविर में प्रभारी एसडीएम बड़गांव मनसुख डामोर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। राजस्व कार्मिकों ने मौके पर जांच कर अपनी रिपोर्ट शिविर में ही प्रस्तुत की। जांच में तथ्य सही पाए जाने पर उपखण्ड अधिकारी ने मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार रास्ते की संशोधित तरमीम करते हुए उसे प्रस्तावित अतिरिक्त खेल मैदान भूमि से बाहर की ओर स्थानांतरित करने के आदेशहाथों हाथ जारी कर दिए। तरमीम आदेश जारी होने के बाद खेल मैदान के विस्तार हेतु अतिरिक्त 0.4600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो जाएगी। इससे स्वीकृत बजट राशि का प्रभावी उपयोग संभव होगा। साथ ही ईसवाल में बेहतर खेल सुविधाएं विकसित होने से यहां की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने और अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के अधिक अवसर मिलेंगे। उक्त कार्य के लिए ग्रामवासियों ने राज्य सरकार एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय और विपश्यना जयपुर के बीच के मध्य एमओयू सम्पन्न

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

कोटा। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के थॉट एंड इन्नोवेशन सेंटर ने अपने छात्रों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने, भावनात्मक स्थिरता और जीवन कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'विपश्यना समिति, जयपुर' के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर निमित्त चौधरी के साथ डीन इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री इंटरेक्शन एंड इंस्टीट्यूट रिलेशन प्रोफेसर रंजन माहेश्वरी, रजिस्ट्रार श्रीमती भावना शर्मा, थॉट एंड इनोवेशन की मुख्य समन्वयक डॉ लता गिदवानी, ओएसडी डॉ अजय शर्मा एवं विपश्यना समिति की ओर से शिवानी कंसल, सौरभ देवनानी, सुखविंदर एवं सुरभि जैन उपस्थित रहे। विवि प्रशासन का मानना है कि तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ मानसिक शांति और एकाग्रता छात्रों को एक बेहतर पेशेवर और इंसान बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस समझौता ज्ञापन से इंजीनियरिंग के छात्रों को एक नया सकारात्मक और ऊर्जावान शैक्षणिक माहौल मिलेगा। कुलगुरु प्रोफेसर निमित्त चौधरी ने कहा कि इस साझेदारी के द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच ध्यान और विपश्यना साधना के माध्यम से तनाव मुक्ति और मानसिक संतुलन का प्रयास किया जाएगा। आज की प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली में छात्रों के बीच तनाव और मानसिक थकान एक बड़ी चुनौती बन गए हैं।

जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक

सौहार्द और सद्भावना के साथ मनाए जाएंगे पर्व

उदयपुर @ पदमावत मीडिया। आगामी मोहर्रम, निर्जला एकादशी एवं जगन्नाथ रथयात्रा के मद्देनजर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक सोमवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आयोजित बैठक में आगामी पर्वों के दौरान शांति, कानून व्यवस्था एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) जितेंद्र ओझा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने सभी समुदायों एवं नागरिकों से पर्वों को आपसी भाईचारे, सौहार्द एवं सामाजिक समरसता के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी त्योहार जिले की गंगा-जमुनी संस्कृति और सामाजिक एकता के प्रतीक हैं तथा इनके आयोजन में सभी का सहयोग आवश्यक है। निर्जला एकादशी और मोहर्रम जैसे बड़े पर्व क्रमशः 25 एवं 26 जून को मनाए जाने हैं। वहीं जगन्नाथ रथ 16 जुलाई को निकाली जाएगी। प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों से आयोजनों की विस्तृत जानकारी ली। इसमें जुलूस एवं शोभायात्रा के रूटचार्ट, स्वयंसेवकों की नियुक्ति, आयोजनों के दौरान सफाई व्यवस्था आदि के बारे में आवश्यक सहयोग की अपील की। मंदिर समितियों, मोहर्रम कमेटी, अंजुमन इस्लामिया आदि के पदाधिकारियों ने अपनी ओर से महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए प्रशासन और पुलिस ने अपेक्षित व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया। एडीएम श्री ओझा ने मोहर्रम एवं जगन्नाथ रथयात्रा के निर्धारित मार्गों पर पेंचवर्क, साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्त, सीसीटीवी कवरेज आदि की जानकारी दी गई। प्रशासन ने सभी पक्षों से सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक सामग्री के प्रसार से बचने की अपील करते हुए सख्त निगरानी की बात कही। बैठक में प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, शांति समिति के सदस्य, मंदिर समितियों एवं मोहर्रम कमेटियों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सुशासन की अनूठी मिसाल: खाखड में ग्रामीण सेवा शिविर बना वरदान

हाथों हाथ मिला पट्टा, पेंशन शुरू होने से बुजुर्गों को मिला संबल

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

उदयपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निदेर्शानुसार चल रहे सेवा शिविर सुशासन की अनूठी मिसाल सिद्ध हो रहे हैं। शिविरों में आमजन को त्वरित राहत मिल रही है। इसकी बानगी उदयपुर जिले की झाड़ोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खाखड में देखने को मिली। खाखड़ में संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में प्रशासन खुद जनता के द्वार पहुँचा, जिससे ग्रामीणों की बरसों से अटकी समस्याओं का समाधान मिनटों में एक ही छत के नीचे हो गया।

बुजुर्गों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

शिविर की सबसे भावुक और प्रेरणादायी तस्वीर तब देखने को मिली जब गाँव की बुजुर्ग महिला जमकु बाई (पत्नी श्री नवला) अपनी वृद्धावस्था पेंशन की समस्या लेकर पहुँचीं। लंबे समय से पेंशन के लिए भटक रही जमकु बाई की फाइल पर शिविर प्रभारी विकास अधिकारी जितेंद्रसिंह राजावत ने तुरंत संज्ञान लिया और मौके पर ही उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का पीपीओ प्रदान किया। पेंशन आदेश पाकर भावुक हुईं जमकु बाई ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें अपने छोटे-मोटे खर्चों के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा । इसी प्रकार, एक अन्य ग्रामीण गणेशलाल पिता नाथु मेघवाल की रुकी हुई पेंशन की समस्या का भी त्वरित समाधान किया गया। जांच में पाया गया कि उनका वार्षिक सत्यापन लंबित होने के कारण पेंशन रुकी थी, जिसे अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर ही सत्यापित किया और पेंशन पुनः बहाल कर दी।

सच हुआ आशियाने के अधिकार का सपना

आशियाने के अधिकार की उम्मीद संजोए बैठे ग्रामीणों के लिए यह शिविर ऐतिहासिक साबित हुआ। पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार मौके पर ही पात्र लाभार्थियों को आवासीय पट्टे वितरितकिए गए । पट्टा हाथ में आते ही लाभार्थी कालूलाल पिता बाबूलाल, मन्नालाल पिता धुला, लोकेश पिता कालू पटेल और निरंजन पिता सुंदर लाल के चेहरों पर सुकून साफ देखा जा सकता था। अब ये ग्रामीण बिना किसी डर के अपने पक्के आशियाने का निर्माण करा सकेंगे और इस पट्टे के जरिए बैंक लोन व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा पाएंगे।

सामूहिक विकास को मिला संबल

व्यक्तिगत लाभ के साथ-साथ गाँव के सामूहिक विकास और सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ाते हुए शिविर में दो महत्वपूर्ण सामुदायिक पट्टे भी जारी किए गए। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खाखड को भूमि का आवंटन कर पट्टा सौंपा गया, जिससे विद्यालय के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को कानूनी मजबूती मिलेगी। वहीं कुल देवी माता मंदिर के पास सामुदायिक भवन हेतु पट्टा जारी किया गया, जिससे अब पूरे गाँव को सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए एक सर्वसुविधायुक्त स्थान मिल सकेगा।

सेवा शिविरों से गांव-शहर पहुंच रहा समाधान, आमजन को मिल रही त्वरित राहत

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

उदयपुर। राज्य सरकार के जनकल्याणकारी अभियान के तहत जिले में आयोजित किए जा रहे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल के निर्देशन में संचालित इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे आमजन को राहत मिल रही है। इसी क्रम में सोमवार को जिले की ग्राम पंचायत चैकड़िया, नाई, भैसड़ाकलां, ईसवाल, गादोली, गोलवाड़ा, तारावट, बगडुन्दा, जेमली, मगवास, खाखड़, उपली सिगरी, निचली सिगरी, बावलवाड़ा, मगरा, थाना, पीपली-बी, रूजियाखूणा, दाडमिया एवं सामोली में सेवा शिविर आयोजित किए गए। वहीं युडीए तथा नगर निकायों में भी शिविर चल रहे हैं। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उपस्थित रहकर आमजन की समस्याएं सुनीं तथा पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले शिविरों में पहुंचकर विभिन्न सरकारी योजनाओं, सेवाओं एवं समस्याओं के समाधान का लाभ उठाएं।

स्वत्वाधिकारी, संस्थापक, प्रकाशक एवं प्रधान सम्पादक : पवन मॉगीलाल जैन उर्फ पवन जैन पदमावत, प्रधान कार्यालय : गणेश नगर, कांदिवली वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र, भारत - 400067 से अमुद्रित ऑनलाईन प्रकाशित। मो. नं. : +91-95945-42679
e-mail :- padmavatmedia@gmail.com / Web : padmavatmedia.in (नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी)। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र मुम्बई, महाराष्ट्र होगा। उक्त ई-पेपर को अवैध रूप से छपवाना कानूनी अपराध हैं।